

दैनिक रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

राज्य पार्टी प्रमुख नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन



मुंबई : राज्य पार्टी प्रमुख नाना पटोले के नेतृत्व में एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उनसे एकनाथ को बर्खास्त करने का अनुरोध किया। राज्य में शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार, "हमें बच्चों के हाथों में हथियार मिले। राज्य में अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा आ रहा है। यह बहुत गंभीर है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जन प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए।" यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहा है," पत्र पढ़ा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने

और कानून-व्यवस्था में समस्याएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पत्र में कहा गया है, "इतने महान महाराष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने को बाधित करने, राज्य में शांति भंग करने का काम किया जा रहा है और इसने कानून-व्यवस्था की एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है।" महाराष्ट्र में हिंसा की कुछ घटनाओं को सूचीबद्ध करते हुए, जैसे कि पूर्व शिवसेना पार्षद अभिषेक घोषालकर की मौत, पत्रकार निखिल वागले पर हमला, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता गणपत गायकवाड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन में गोलीबारी की घटना, पत्र में कहा गया है कि ये घटनाएँ "चिंताजनक" हैं और इसने राज्य में एक बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी है।

16 साल के बाद, कोर्ट ने मामले में फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया



मुंबई: 2008 के मालेगांव विस्फोट के सोलह साल बाद, विशेष एनआईए अदालत ने फरार आरोपी रामचंद्र कलसांगरा की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है क्योंकि वह मुकदमे के लिए खुद को पेश करने में विफल रहे। कलसांगरा पर मालेगांव में एक मस्जिद के पास विस्फोटक से भरी बाइक रखने का आरोप है। यह बाइक कथित तौर पर भाजपा सांसद प्रजा ठाकुर की थी। 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 101 घायल हो गए थे। विस्फोट के बाद कलसांगरा फरार हो गया है। अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है और कलसांगरा को भगोड़ा घोषित कर दिया है क्योंकि वह अदालत में पेश नहीं हुए।

अजित पवार की मौजूदगी में बाबा सिद्दीकी एनसीपी में हुए शामिल



मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें बाबा सिद्दीकी के नाम से जाना जाता है, शनिवार, 10 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, एनसीपी प्रमुख की उपस्थिति में एनसीपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के अन्य नेता। लगभग 48 वर्षों तक पार्टी के वफादार रहे बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। "मैं एक युवा किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट का किया रुख, लगाए ये आरोप

मुंबई: एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने उनके खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज किये गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि उनके द्वारा एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद बदले की भावना से यह मामला दर्ज किया गया है।



न्यायमूर्ति पी. डी. नाइक की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश की जा सकती है। वानखेड़े को सीबीआई मामले में पिछले साल उच्च न्यायालय की ओर से दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी।

शिकायत की जांच करने में विफल रही पुलिस

वानखेड़े ने ईडी मामले के खिलाफ दायर याचिका में दावा किया कि ईसीआईआर (प्रवर्तन सूचना रिपोर्ट) पिछले साल दर्ज की गई थी, जबकि वानखेड़े द्वारा पिछले माह दिल्ली की एक अदालत में एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराने के बाद अब जाकर मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के कई अधिकारियों को समन जारी किया गया है। वानखेड़े ने दावा किया कि दिल्ली और मुंबई पुलिस दोनों ही सिंह के खिलाफ उनकी शिकायत की जांच करने में विफल रहीं, ऐसे में उन्हें दिल्ली में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दिल्ली की एक अदालत ने 6 फरवरी को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर वानखेड़े की शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

ईडी ने मादक पदार्थ संबंधी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया। भारतीय राजस्व सेवा में सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर काडर के 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े ने अपनी याचिका में कहा कि ईडी का मामला दुर्भावना और प्रतिशोध से युक्त है।

हाईकोर्ट से लगाई गुहार

अधिवक्ता करण जैन, स्नेहा सनप

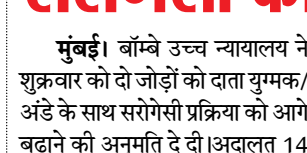
और आदित्य तडगे के माध्यम से 6 फरवरी को दायर याचिका में ईडी के मामले को रद्द करने और उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हुये एक अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। वानखेड़े ने यह भी अनुरोध किया है कि जब तक सीबीआई के मामले के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई और फैसला नहीं हो जाता, तब तक ईडी द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी जाए। सीबीआई और ईडी के खिलाफ उनकी याचिकाएं सुनवाई के लिए 15 फरवरी को

मुंबई में इमारत का एक हिस्सा ढहने से दो ऑटोरिक्शा चालक घायल



मुंबई : महाराष्ट्र में मुंबई के बोरीवली इलाके में पुरानी इमारत के ढांचे को ध्वस्त करने के दौरान उसका एक हिस्सा ढह जाने से दो ऑटोरिक्शा चालक घायल हो गए और उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना दोपहर में उपनगर में गणेश मंदिर के पास नैन्सी कॉलोनी में तब हुई जब एक तीन मंजिला इमारत को तोड़ा जा रहा था। उन्होंने बताया कि इमारत पहले से ही खाली थी। अधिकारी के अनुसार, इमारत का कंक्रीट से निर्मित एक बड़ा हिस्सा बगल की सड़क पर दो ऑटोरिक्शा पर गिर गया जिससे चालक रविकुमार लखनकुमार राणा (45) और सुमन शुक्ला (34) घायल हो गए।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने डोनर गैमेट्स के साथ सरोगेसी की अनुमति दे दी



मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दो जोड़ों को दाता युग्म/अंडे के साथ सरोगेसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। अदालत 14 मार्च, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना को चुनौती देने वाले दो जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरोगेसी के लिए केवल जोड़े के युग्मकों के उपयोग की अनुमति दी गई थी और दाता युग्मकों को अस्वीकार कर दिया गया था। पहले जोड़े के मामले में, पत्नी क्रोमोसोमल दोष से पीड़ित थी। दूसरे जोड़े के मामले में, पत्नी का गर्भपात हो गया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि अधिसूचना जारी होने के बाद से मुंबई में एक भी सरोगेसी नहीं हुई है। अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने तीन सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किए और पीठ को सूचित किया कि उन्होंने सरोगेसी याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए राज्य सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी

बोर्ड की स्थापना की है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 18 अक्टूबर, 2023 के आदेश का पालन किया, जिसके द्वारा उसने याचिकाकर्ता जोड़े के संबंध में केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी, अधिसूचना को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित थी। शीर्ष अदालत ने दंपति को सरोगेसी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दे दी थी। पीठ ने नवंबर 2023 के कर्नाटक एचसी के आदेश पर भी गौर किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अधिसूचना को चुनौती देते हुए 10 से अधिक जोड़ों को सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति दी थी।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

संतुलित दृष्टिकोण

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के वर्ष 2020-21 और 2021-22 के आंकड़े जारी कर दिए। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से मची उथल पुथल से जूझ रही थी। बहरहाल, परिणाम दिखाते हैं कि देश का विनिर्माण क्षेत्र कच्चे माल के इस्तेमाल, उत्पादन और मुनाफे के मामले में मजबूत है। एएसआई पूरे देश में विस्तारित है और यह औद्योगिक आंकड़ों का सबसे प्रमुख स्रोत है। यह 10 या अधिक कर्मचारियों वाली और बिजली का इस्तेमाल करने वाली तथा बिना बिजली की खपत वाली लेकिन 20 से अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों को गणना में लेती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17 फीसदी है। समीक्षा अवधि में जहां देश के औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा, वहीं इसका अपेक्षाकृत छोटा पैमाना और सघनता चिंता का विषय है। विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्यवर्द्धन में वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 में मौजूदा दरों पर क्रमशः 8.8 फीसदी और 26.6 फीसदी की वृद्धि हुई। उत्पादन में कमी के बावजूद 2020-21 में सकल मूल्यवर्द्धन में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई थी। यह बात ध्यान देने लायक है कि उत्पादन में केवल वित्त वर्ष 21 में ही गिरावट नहीं आई बल्कि उसके पिछले वर्ष भी इसमें गिरावट आई थी जबकि वित्त वर्ष 22 में इसने वापसी की। रोजगार के संदर्भ में बात की जाए तो अनुमान के मुताबिक ही वित्त वर्ष 21 में इसमें मामूली कमी आई। परंतु अगले वर्ष इसकी अच्छे से भरपाई हो गई और रोजगार में सालाना आधार पर सात फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इस क्षेत्र में प्रति कर्मचारी औसत क्षतिपूर्ति में भी सर्वेक्षण में शामिल दो वर्षों के दौरान इजाफा देखने को मिला। इसके अलावा महामारी ने नियोजित पूंजी को भी प्रभावित नहीं किया। स्थायी पूंजी और निवेश की गई पूंजी दोनों में संदर्भ अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली। इन सब बातों के बीच विनिर्माण गतिविधि भौगोलिक रूप से कुछ खास इलाकों तथा चुनिंदा उत्पादों में सिमटी हुई है। एएसआई के परिणामों ने दिखाया कि केवल पांच राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 21 और 22 में विनिर्माण के कुल मूल्यवर्द्धन में 50 फीसदी से अधिक योगदान किया। इसके साथ ही बुनियादी धातु, कोयला और रिफाइनड पेट्रोलियम, फार्मास्युटिकल उत्पाद, वाहन, खाद्य और रासायनिक उत्पाद उद्योगों ने मिलाकर इस क्षेत्र के कुल मूल्यवर्द्धन में 56 फीसदी का योगदान किया। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के बावजूद वित्त वर्ष 22 में विनिर्माण क्षेत्र में 1.7 करोड़ से कुछ अधिक लोग ही रोजगारशुदा हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। हम विनिर्माण क्षेत्र में इतने अधिक रोजगार नहीं तैयार कर सके हैं कि लोगों को कृषि कार्यों से बाहर निकाल सकें क्योंकि वहां उत्पादकता बहुत कम है। सरकार ने अपनी ओर से हस्तक्षेप किया है और निवेश बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में कम कॉर्पोरेशन कर, सिंगल विंडो मंजूरी और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना आदि की पेशकश की है। यह उम्मीद भी की जा रही है कि वैश्विक कंपनियों द्वारा चीन से दूरी बनाने का नतीजा भारत में अधिक निवेश के रूप में सामने आएगा। यद्यपि अब तक इस दिशा में सीमित सफलता मिली है। भारत को लगातार निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। सरकार के सामने न केवल उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए उच्च निवेश की आवश्यकता है बल्कि उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निवेश गिनेचुने राज्यों तक सीमित नहीं रहे। औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के क्षेत्र में एकराफ झुकाव वाली वृद्धि संघीय व्यवस्था में तनाव पैदा कर सकती है। अलग-अलग रूप में यह नजर भी आने लगा है।

शिवसेना के विधायक ने स्कूली बच्चों से दिया अजीबो-गरीब बयान

हिंगोली : कलामनुरी निर्वाचन क्षेत्र से मनमौजी शिवसेना शिदि गुट के विधायक संतोष एल. बांगर ने अक्टूबर 2024 के आसपास होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समय पूर्व अभियान के दौरान एक बार फिर सत्तारूढ़ महायुति सरकार को शर्मसार किया है। खुद बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देने वाले 43 वर्षीय बांगर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लख गांव में एक प्राथमिक विद्यालय के 10 साल से कम उम्र के लगभग 50 छात्रों की एक बैठक को 'संबोधित' किया। उन्होंने स्कूली बच्चों के सामने एक अजीब भाषण दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर उनके माता-पिता अगले चुनाव में उन्हें (बांगर को) वोट नहीं देते हैं तो वे दो दिन तक खाना न खाएं। बांगर को बच्चों से लगभग कठोर स्वर में कहते सुना गया, "यदि आपके माता-पिता आपसे पूछते हैं कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, तो उन्हें बताएं कि भूख अनशन तोड़ने से पहले उन्हें 'संतोष बांगर' के लिए

वोट करना होगा।" उन्होंने छोटे-छोटे संकोची बच्चों से ऊंचे समवेत स्वर में कम से कम तीन बार अपना नाम 'संतोष बांगर' बुलवाया, यहां तक कि आसपास खड़े उनके समर्थकों और कुछ स्कूल शिक्षकों को अपनी हंसी रोकनी पड़ी। बांगर की हरकतों पर तुरंत ही विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के नेताओं ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने वोट हासिल करने के लिए छोटे बच्चों का 'शोषण' करने के लिए बांगड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के विजय वडेटीवार ने सत्तारूढ़ विधायक की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बच्चों को उकसाया कि अगर उनके माता-पिता उन्हें (बांगर) को वोट नहीं देते हैं तो वे कुछ दिनों के लिए खाना न खाएं। नाराज वडेटीवार ने कहा, "भारतीय चुनाव आयोग के राजनीतिक प्रचार या किसी भी चुनाव संबंधी कार्यों के लिए बच्चों का उपयोग न करने के आदेश के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक प्रचार के लिए एक स्कूल में जाकर ऐसा कर रहे हैं।"



6,600 करोड़ का बित्काइन घोटाला: ईडी की जांच अभी भी अधूरी..



मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली स्थित भारद्वाज परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने के छह साल बाद भी, वह अभी तक क्रिप्टोकॉइन्स का उपयोग करके बनाई गई क्रिप्टो संपत्तियों को समझने में सक्षम नहीं हो पाया है। इस मामले में मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और उनके दिवंगत भाई अमित भारद्वाज हैं। वैरिबलटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के निदेशकों पर निवेशकों को बित्काइन और इस कंपनी द्वारा विकसित क्रिप्टोकॉइन्स में बहुत अधिक रिटर्न का वादा करके बित्काइन में निवेश करने के लिए लुभाने का आरोप है। ईडी वैरिबलटेक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है, जिसमें कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी के 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। ईडी ने दावा किया है कि भारद्वाज परिवार के सदस्यों ने अन्य बहु-स्तरीय विपणन एजेंटों और सहयोगियों के साथ भोले-भाले निवेशकों से 80,000 बित्काइन (नवंबर 2017 तक 6,606 करोड़ रुपये) एकत्र किए हैं।

ईडी ने अपनी जांच में दावा किया कि भारद्वाज परिवार ने इन बित्काइन को विभिन्न अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया है, जिसका खुलासा आज भी उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ईडी ने पिछले महीने अजय की पत्नी

सिम्पी को गिरफ्तार किया था, जबकि वह और उसके पिता फरार हैं। सिम्पी पर उनके भागने में मदद करने का आरोप है। एजेंसी ने परिवार की आयकर फाइलों को देखा, जिसमें यह पता चला कि सिम्पी की अ 2021-2022 के लिए घोषित आय 2.88 लाख रुपये प्रति वर्ष है, जबकि इसी अवधि के लिए उनके पति अजय की घोषित आय 3.10 लाख रुपये है। इसी अवधि के लिए उनके ससुर महेंद्र की घोषित आय 4.35 लाख रुपये है। एजेंसी ने कहा कि उनकी कुल आय उनके मासिक खर्च से बहुत कम है, जो रूढ़िवादी नोट पर 6 लाख रुपये प्रति माह से अधिक होगा।

वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मराठे का जन्म दिन मनाया



मुंबई : मुंबई नावाट्ट के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मराठे का 42 जन्म दिन आज मुंबई आरपीआई कार्यालय में पत्रकारों ने मिलकर मनाया। जिसमें प्रमुख रूप से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले केंद्रीय कार्यालय में रिपाई म्युनिसिपाल यूनिशन के नेता व उत्तर पश्चिम जिला अधक्षय प्रकाश कमलाकर जाधव व दक्षिण मुंबई जिला प्रधान सचिव शिरिष भाई चिखलकर, तालुका अधक्षय विशाल

गायकवाड, म्युनिसिपाल कामगार नेता बाबू कोस्टा, कार्यालय सचिव दादा साहेब जाधव, विनोद कंबले, सुरेश गायकवाड, आठवले गुट के एस के शर्मा, सलीम सैयद, यशपाल शर्मा, रवि यादव, शिरिष वानखेड़े, सलीम खातीब, फिरोज सिद्दीकी, की उपस्थिति में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मराठे का 42 वा जन्म दिन केक काटकर उत्साह पूर्वक धूम धाम से मनाया।

मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व खिलाड़ी और मैनेजर ओले गुन्नार सोलस्कर मुंबई पहुंचे...

मुंबई : मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व खिलाड़ी और मैनेजर ओले गुन्नार सोलस्कर अपने पहले भारत दौरे के दौरान शनिवार को मुंबई पहुंचे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, ओले का कई यूनाइटेड प्रशंसकों ने स्वागत किया। नॉर्वेजियन ने उन्हें निराश नहीं किया और सेल्फी ली और उनकी जर्सी पर हस्ताक्षर किए। भारत मैनचेस्टर यूनाइटेड के वैश्विक प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या का घर है, ऐसे में सोलस्कर की यात्रा देश भर में टीम के समर्थकों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।

"मैं वास्तव में यहां भारत आकर और देश के रेड डेविल्स से मिलकर

बहुत रोमांचित हूं। उन्होंने कहा कि यह दौरा न केवल प्रशंसकों के लिए बल्कि उनके लिए भी एक "यादगार क्षण" है। सोलस्कर ने आयोजकों द्वारा साझा किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा, "मैं देश का दौरा करने और इसकी फुटबॉल संस्कृति का अनुभव करने के लिए उत्सुक हूं। मैं बेंगलुरु में मिले गर्मजोशी से स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं और दिल्ली और मुंबई में प्रशंसकों से मिलने का उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं।"

"मुझे टचलाइन के दोनों तरफ फुटबॉल के जादू का अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए, प्रशंसकों के साथ उन आखिरी मिनट के लक्ष्यों और अविस्मरणीय जीत

को याद करने में सक्षम होना हमेशा खुशी की बात है। जबकि मैंने केवल भक्ति के बारे में सुना था सोलस्कर ने कहा, "मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रति भारतीयों का रुझान, आज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का अवसर मिलना अविश्वसनीय था।" दौरे के बेंगलुरु चरण के बाद, उनकी यात्रा यह सुनिश्चित करेगी कि फुटबॉल प्रशंसकों को नॉर्वेजियन से मिलने का मौका मिलेगा, जो शनिवार को मुंबई में और 11 फरवरी को नई दिल्ली में भव्य रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। ओले ने अपने पहले भारत दौरे की शुरुआत बेंगलुरु और मुंबई से की और 11 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करेंगे।

+91 99877 75650
editor@rokhoklekhani.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

कंटेनर और कार की टक्कर में तीन लोगों की मौत



मुंबई: अहमदनगर जिले के कोपरगांव के धोतर गांव के पास कल रात एक कंटेनर और कार की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो लोग घायल हो गए और उन्हें कोपरगांव ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोपरगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक संदीप कोली के अनुसार, जालना जिले के निवासी राहुल राजभोज अहमदनगर जिले के शिरडी की ओर जा रहे थे। कोपरगांव के धोतर गांव के पास अचानक उनकी कार सड़क पर खड़े एक कंटेनर से टकरा गई। इस घटना में राहुल राजभोज, उमेश उगले और भाऊसाहेब पथेन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

एंटी-नारकोटिक्स सेल ने जब्त की 15 करोड़ रुपये की ड्रग्स



मुंबई : एंजेसी ने कहा कि अपराध शाखा, मुंबई के एंटी-नारकोटिक्स सेल ने अलग-अलग घटनाओं में 3 प्रकार की दवाएं जब्त कीं और सात ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। 5.735 किलोग्राम एमडी (मेफेट्रोन) जिसकी कीमत रु. सांताक्रूज और वसोर्वा (अंधेरी) क्षेत्र से 11.46 करोड़ रुपये, कुर्ला पूर्व और बांद्रा पूर्व क्षेत्र से 500 ग्राम हेरोइन (2 करोड़ रुपये मूल्य) और 3 किलोग्राम चरस रुपये जब्त किए गए। दहिसर चेक नाका इलाके से 1.20 करोड़ रुपये जब्त किये गये।

सांताक्रूज और वसोर्वा क्षेत्र में पहली घटना में, सोमवार को जब्ती की गई। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी कर्नाटक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक है और वह राजस्थान का रहने वाला है। बांद्रा ईस्ट और कुर्ला ईस्ट इलाके में गुरुवार को ये जब्ती की गई। वहां एएनसी अधिकारियों ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को 350 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा और घर की तलाशी में 150 ग्राम हेरोइन बरामद की। जांच के दौरान पता चला कि एक आरोपी उत्तराखंड राज्य से मुंबई क्षेत्र में हेरोइन बेचने आया था।

दहिसर चेक नाका क्षेत्र में, एएनसी अधिकारियों ने 3

किलोग्राम मनाली चरस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि गिरफ्तार आरोपी गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले का रहने वाला है। उपरोक्त सभी मामलों में, नेटवर्क की पहचान के साथ-साथ आपत्तिजनक विवरण निकाले गए। एंजेसी ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय सदस्यों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।

एंजेसी ने कहा, 2023 में एएनसी-मुंबई ने 53 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया और 229 प्रमुख ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 14 नाइजीरियाई और दो तंजानिया के नागरिक थे। इसमें कहा गया है कि 2024 में एएनसी-मुंबई ने 20.18 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के 15.95 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए और 27 प्रमुख ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

छगन भुजबल को जान से मारने की धमकी..

मुंबई: मराठा आरक्षण और ओबीसी विवाद के बीच छगन भुजबल को जान से मारने की धमकी मिली है। भुजबल के नासिक कार्यक्रम में एक गुमनाम पत्र आया है इसमें जान से मारने की बात लिखी है। पत्र को लिखने वाले व्यक्ति ने कहा है कि उसने हत्या की सुपारी ली है। पत्र में लिखा गया है कि आपको भुजबल को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मार दिया जाएगा। शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पत्र जांच शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भुजबल के समर्थकों ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है।



गया कि यह ठेका 50 लाख रुपये में पांच लोगों को दिया गया है।

छगन भुजबल एनसीपी कोटे से मंत्री हैं। वे जुलाई 2023 में अजित पवार के साथ महायुति सरकार में शामिल हो गए थे। तब से वह मंत्री हैं। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी विधायक छगन भुजबल को 9 फरवरी को जान से मारने की धमकी मिली। एक अज्ञात व्यक्ति ने नासिक स्थित उनके कार्यालय में पत्र भेजकर उन्हें जान से मारने की सुपारी देने की जानकारी दी। पत्र में दावा किया

स्थानीय पुलिस पत्र की जांच कर रही है और यह भी देख रही है कि क्या अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत है। भुजबल ने पिछले साल दिसंबर में भी विधानसभा में एक सनसनीखेज दावा किया था, जिसमें कहा गया था कि पुलिस इनपुट है कि उन्हें 'गोली मारकर हत्या' की जा सकती है और उन्होंने खुलासा किया कि मराठा आरक्षण के लिए चल रहे आंदोलन के बीच उन्हें पिछले दो महीनों से गालियां और धमकियां मिल रही हैं। मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी सर्टिफिकेट देकर आरक्षण देने का भुजबल विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है मराठा को सरकार आरक्षण दे, लेकिन मौजूदा आरक्षण में नहीं शामिल किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री के अगल-बगल गुंडे फिरते हैं हमने देखा है - नाना पटोले

मुंबई: महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले ने राज्य के कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला है। पटोले ने कहा, महाराष्ट्र सरकार लोगों को गोली मारने का काम कर रही है। सत्ता का मतलब चोरी करना नहीं सबको सुरक्षा और सुविधा देना है। कल की घटना काफी डरावनी थी। पुलिस स्टेशन में जो गोलीबारी हुई वो बहुत खतरनाक है। ये सरकार बेजवाबदार है। इस सरकार ने महाराष्ट्र की दुर्गाति कर डाली है। कल हम राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बर्खास्त करने की अपील करेंगे। इस सरकार में न तो किसान खुश हैं न लोग खुश हैं और न ही महिलाएं सुरक्षित हैं। ये सरकार का गुंडाराज है। मुख्यमंत्री के अगल-बगल गुंडे फिरते हैं हमने देखा है।



की नजर है। बड़ी मात्रा में लूट चालू है। ये लूटपाट में जनता मुसीबत में है। जिसका ज्यादा गुंडा राज है उसका प्रमोशन होता है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता मानती थी और मानती है। यह जनता राहुल गांधी को सत्ता में लायेगी। महाराष्ट्र में बहुमत से कांग्रेस आयेगी। उस दिन मुख्यमंत्री ने मनोज जरागे पाटिल को नींबू शरबत

पिलाकर उनका भूख हड़ताल खत्म कराया। उस वक्त वहां सिर्फ मुख्यमंत्री गए, उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस नहीं गए। कीर्तन भजन ये सब से देश नहीं चलेगा। पटोले ने उल्हासनगर में हुई बीजेपी विधायक के गोलीकांड का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता ने कहा, पुलिस स्टेशन में बैठकर फायरिंग करना, 5-5 गोलियां चलाना ये सब काम करती है बीजेपी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ + सिक्वोरिटी देकर उनको बढ़ावा दिया गया है। लोगों के घर से विधायक चुराना पार्टी बढ़ाना ये सब करती है बीजेपी। ये विभिन्न भाषाओं का देश है फिर भी हम एक हैं।

IAS पति के खिलाफ पत्नी ने लगाई याचिका... हाई कोर्ट ने की खारिज

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने पति, एक आईएएस अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईआर केवल पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के प्रतिवाद के रूप में दर्ज की गई थी 19 फरवरी को जस्टिस एएस चंडुरकर और जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा, "यह एक आदर्श मामला है जहां इस न्यायालय को न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के



लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए।" एचसी पति और उसके परिवार, मां, भाई और बहन द्वारा अधिवक्ता एसआर नारगोलकर, अर्जुन कदम और नीता पाटिल के माध्यम से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी न्यायिक अधिकारी की मुलाकात उसके पति से एक वैवाहिक साइट के माध्यम से हुई और उन्होंने फरवरी 2018 में शादी कर ली। पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी

के बाद, पति ने उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया और उनके बीच विभिन्न वैवाहिक विवाद हुए। पत्नी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि पति द्वारा विविध याचिका दायर करने के बाद, वह और उसका भाई 7 जून, 2023 को उसके न्यायिक कक्ष में दाखिल हुए और उसे आपसी सहमति से तलाक की याचिका पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी। उसने कथित तौर पर आपसी सहमति से तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया। उसी दोपहर, उसकी मां और बहन भी उसके चैंबर में आईं और उसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकी दी।

10 साल से छोटे बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स में बदलाव करने के निर्देश

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कारणों से 10 साल से छोटे बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए निर्देश जारी किया राज्य के सभी प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों में 10 साल के कम उम्र के बच्चों की कक्षाएं सुबह 7 बजे की बजाय 9 बजे से शुरू की जाएं। यह निर्देश

सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को भी दिए गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने 2 महीने पहले 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सुबह 7 बजे से स्कूलों की कक्षाएं शुरू होने पर चिंता जतायी थी। स्कूलों के समय में बदलाव से जुड़ा फैसला राज्यपाल के उसी व्याख्यान से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य

सरकार ने यह निर्णय लेने से पहले, स्कूल के समय परिवर्तन प्रस्ताव पर एक सर्वे भी कराया। इस सर्वे में बच्चों के माता-पिता और शिक्षकों, शिक्षा जगह से जुड़े विशेषज्ञों और अन्य एक्सपर्ट्स की भी सलाह ली। सर्वेक्षण करवाने के बाद ही सुबह शुरू होनेवाले स्कूलों के समय में बदलाव का यह निर्णय लिया गया। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि शहरों

और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कक्षाएं सुबह 7 बजे शुरू किए जाने के नियम पर एक बार विचार करने की सलाह लोगों ने दी थी। बच्चों के लिए नौद की कमी बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है क्योंकि इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास स्लो हो सकता है। कुछ समय पहले इटली में इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस ऑफ द नेशनल रिसर्च काउंसिल द्वारा की

गयी एक रिसर्च में कहा गया कि 16 साल तक के बच्चों को दिन में 8-9 घंटे की नौद लेना आवश्यक है। वहीं, 10 साल से छोटे बच्चों की नौद पूरी ना होने से उन्हें बिहेवियर, इमोशनल हेल्थ और ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इस रिसर्च के अनुसार नौद की कमी से बच्चों को इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं-

भारतीय अंतरिक्ष यात्री जल्द ही जाएगा चांद पर...

इसरो के साइंटिस्ट ने बताई अहम योजना



उदगमंडलम : इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के परियोजना निदेशक पी. वीरमथुवेल ने शनिवार को कहा कि 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को पहुंचाने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वीरमथुवेल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इसरो अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाना चाहिए और

2035 तक हमारा अंतरिक्ष स्टेशन भी होना चाहिए। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिन्हें इसरो ने शुरू किया है। हम इन योजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

मिशन के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया

चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन माड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में वापस लाने में इसरो की सफलता पर वीरमथुवेल ने कहा, जहां तक चंद्रयान-3 का सवाल है, 'लैंडर' और रोवर मिशन ने सफलतापूर्वक एक चंद्र दिवस पूरा किया। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि प्रोपल्शन माड्यूल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

मनोज जारंगे पाटिल ने मराठा आरक्षण को लेकर एक और अनिश्चितकालीन मुख्य हड़ताल शुरू की



जालना: मराठा आरक्षण के लिए दबाव बनाने के लिए कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने शनिवार को महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने गांव, अंतरवाली-सरती से एक और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। पाटिल ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार अगले दो दिनों में एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाए। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए दिए गए मसौदा अधिसूचना को लागू करने के लिए इसे विशेष विधानसभा सत्र में कानून बनाया जाना चाहिए।" पाटिल ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार मराठा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करे। इससे पहले, पाटिल ने बुधवार को घोषणा की थी कि वह 10 फरवरी से एक

और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा, "फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की बहुत जरूरत है। आरक्षण के लिए कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। मराठा समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 'पाटिल ने कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार जब उन्हें आरक्षण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो वे विजय रैली करेंगे और उस दिन को 'महा दिवाली' के रूप में मनाया जाएगा। "पिछले 70 वर्षों में यह पहली बार है कि मराठा समुदाय

के पास आरक्षण के लिए एक मजबूत कानून है। हमने मुंबई तक मार्च करने की योजना बनाई थी। जब हमें आरक्षण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो हम एक विजय रैली आयोजित करेंगे और वह दिन होगा।" महा दिवाली के रूप में मनाया जाता है, "उन्होंने कहा। भले ही राज्य सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर मराठा समुदाय को आरक्षण देने का दावा किया है, लेकिन नेताओं द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों के बाद जारंगे पाटिल और उनका समुदाय संदेह में हैं।

जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। हालांकि, कुंबी श्रेणी के तहत आरक्षण की गारंटी पर महाराष्ट्र सरकार के भीतर आपत्ति है और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इसका विरोध किया है। "मैं पिछले 35 वर्षों से ओबीसी के लिए काम कर रहा हूँ। आज मराठा ओबीसी में शामिल हैं, कल पटेल, जाट और गुर्जर भी शामिल हो जाएंगे। मजबूत समुदाय इस तरह ओबीसी श्रेणी में प्रवेश करेंगे। हम हर संभव तरीके से लड़ेंगे।" लोकतंत्र में उम्मीद की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा पिछड़े नहीं हैं, लेकिन उन्हें पिछड़े दर्जा से ओबीसी में शामिल किया जा रहा है, इससे ओबीसी आरक्षण प्रभावित हो रहा है," भुजबल ने कहा था।

महाराष्ट्र में प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है - DGP रश्मि शुक्ला

मुंबई: महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने राज्य की जनता को संबोधित एक पत्र लिखा है। पुलिस महानिदेशक ने खुद स्वीकार किया है कि पुलिस बल (महाराष्ट्र पुलिस) पर जनता का विश्वास कम हो गया है। रश्मि शुक्ला का यह पत्र तब चर्चा में है जब प्रदेश में कानून व्यवस्था की समस्या है। रश्मि शुक्ला ने पत्र में कहा है कि पिछली गलतियों को पीछे छोड़कर आपका विश्वास जीतना हमारी जिम्मेदारी है। रश्मि शुक्ला ने पत्र में लिखा कि मेरी प्राथमिकता पूरे महाराष्ट्र में प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।



अधिकारों की रक्षा के लिए तत्परता से काम करते रहेंगे। रश्मि शुक्ला राज्य की पहली महिला आईपीएस हैं जो डीजीपी की पोस्ट पर पहुंची हैं। डीजीपी का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राज्य में ठाणे में बीजेपी विधायक के गोलीकांड और दहिसर में शिवसेना यूबीटी नेता की हत्या के बाद विपक्ष हमलावर है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता

और नेता विपक्ष विजय नामदेवराय वडेट्टीवार शवसेना (यूबीटी) के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद कानून-व्यवस्था पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कहा कि महाराष्ट्र में कानून बचा ही नहीं है और क्रिमिनल की हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा था कि पूरे महाराष्ट्र में गुंडा राज और माफिया राज चल रहा है और इनको शिदे सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है। क्लाइड क्रास्टो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो चुकी है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को किया संबोधित तीन तलाक और धारा 370 पर भी की चर्चा

नई दिल्ली: राम मंदिर पर शनिवार को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान नेताओं ने लोकसभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। युवा हो या महिला, मंदिर हो या कानून सभी पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। इस दौरान राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी कहा कि राम मंदिर का प्रस्ताव बहुत अहम है। राम मंदिर पर कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग गए। राम मंदिर में सबका साथ, सबका विकास का तत्व है। चुनाव आने वाले हैं, कुछ लोगों में घबराहट है। हमारे



चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले हैं। **लोकसभा में इन मुद्दों पर पीएम मोदी ने की चर्चा**
इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने लोकसभा में सदन के सभी सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि आज का दिन सदन में बेहद अहम है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर

ओम बिरला के धैर्य की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, बिरला जी का चेहरा हमेशा ही मुस्कुराता रहता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये 5 साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के थे। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि अपनी आंखों के सामने रिफॉर्म और परफॉर्म देख सकें। उन्होंने इस दौरान देश की 17वीं लोकसभा को आशीर्वाद और धन्यवाद दिया। धारा 370 पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय किया। आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। हमने धारा 370 हटाकर संविधान की खाई हटाई। हमने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए। इस दौरान उन्होंने नारी वंदन अधिनियम, तीन तलाक और आतंकवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि नए सदन में दूरगामी निर्णय हुए हैं। इस सत्र में नारी वंदन अधिनियम बनाकर पास हुआ। मुस्लिम बेटियों को हमने न्याय दिलवाया। मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति मिली। पीएम ने ये भी कहा कि आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का सपना पूरा करेंगे।

100 साल पुराने ससून अस्पताल में लगी भीषण आग... दमकल की गाड़ियां मौके पर

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे जिले के ससून अस्पताल में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। अभी किसी तरह के जानमाल नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। इस खबर पर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा



है। पुणे के 100 साल पुराने ससून अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई है।

घटना रात करीब 8 बजे हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति ने सिगरेट पीकर उसे वार्ड में एक मरीज के बिस्तर पर छोड़ दिया था, जिससे आग लग गई। हालांकि, वार्ड के मरीजों को समय रहते सुरक्षित जगह ट्रांसफर कर दिया गया था। अभी तक किसी के मरने की खबर सामने नहीं आई है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सपप नं 7977408589: Email-editor@rookthoklekhaninews.com